वर्ष-1 , अंक-4 | बेंगलुरु, शनिवार, 22 अगस्त 2026 | RNI NO:KNHIN/26/A5540 | Contact:news@bhaarataarth.com | पृष्ठ - 4 ,मूल्य - 5 रुपए

दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

ख़बर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

PM मोदी की सचिवों को दो टूक, साइलो तोड़कर साथ काम करें विभाग

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली 21 अगस्त 2026। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक कर सरकारी कामकाज में बेहतर तालमेल और दीर्घकालिक सोच पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच कामकाज में बनी रहने वाली साइलो मानसिकता को खत्म करने की जरूरत बताई और कहा कि सरकार के सभी विभागों को एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। साइलो खत्म कर बढ़ाना होगा समन्वय प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी हो या राष्ट्रीय सुरक्षा–हर क्षेत्र में भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी होंगी। अलग-अलग विभागों में तालमेल की कमी विकास की गति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। कोरोना काल का उदाहरण देकर समझाया

बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कामकाज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उस कठिन दौर में विभिन्न मंत्रालयों ने एकजुट होकर संकट का सामना किया था। इसी तरह का समन्वित कार्य-तंत्र सामान्य परिस्थितियों में भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे से विचार-विमर्श करने और किसी भी तरह की विभागीय दूरी को काम के रास्ते में बाधा नहीं बनने देने की अपील की। अकऔर डेटा पर बढ़े फोकस की जरूरत प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी निगरानी और कामकाज में अक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा कि भविष्य में डेटा एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए भी विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है।

मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट में बेहतर संपर्क प्रधानमंत्री ने विनिर्माण इकाइयों और निर्यात केंद्रित इकाइयों के बीच बेहतर संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय एक ही सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए अलग-अलग दृष्टिकोण के बजाय साझा और समन्वित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों और कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ केवल औपचारिक बातचीत तक सीमित न रहने की सलाह दी। बेहतर व्यक्तिगत संवाद और मजबूत नेटवर्क से कामकाज में सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

पोर्ट डेवलपमेंट से पोर्ट-लेड डेवलपमेंट की ओर प्रधानमंत्री ने भारत में बंदरगाह विकास की अवधारणा से आगे बढ़कर पोर्ट-लेड डेवलपमेंट पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री बुनियादी ढांचे की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए विनिर्माण और निर्यात केंद्रित इकाइयों के बीच मजबूत संपर्क विकसित करने की जरूरत बताई। बैठक में सचिवों ने सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट रहा कि तेज और टिकाऊ विकास के लिए विभागों के बीच दीवारें नहीं, बल्कि मजबूत समन्वय और साझा जिम्मेदारी जरूरी है।

मॉरीशस को भारत का बड़ा तोहफा, 5 साल तक मिलेगा पेट्रोल-डीजल

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026। भारत और मॉरीशस ने अपने पुराने और भरोसेमंद रिश्तों को ऊर्जा क्षेत्र में नई मजबूती दी है। दोनों देशों ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इसके तहत इंडियन ऑयल और मॉरीशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (STC) के बीच पांच वर्ष का करार हुआ है, जिसके तहत मॉरीशस को पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित और सुनिश्चित आपूर्ति की जाएगी। पेट्रोल-डीजल से ATF तक सप्लाई पांच वर्षीय समझौते के तहत इंडियन ऑयल मॉरीशस को पेट्रोल, डीजल, मरीन गैस ऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की आपूर्ति करेगा। इससे मॉरीशस की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने के साथ ईंधन की उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, यह समझौता मॉरीशस की परिवहन व्यवस्था, कनेक्टिविटी और आर्थिक

विकास को भी समर्थन देगा। दक्षिण एशिया के बाहर भारत का पहला 'व्हाइट ऑयल' समझौता

भारत के लिए इस समझौते की एक खास अहमियत भी है। इंडियन ऑयल और STC मॉरीशस के बीच व्हाइट ऑयल की आपूर्ति के लिए हुआ यह करार दक्षिण एशिया के बाहर भारत का इस तरह का पहला समझौता बताया गया है। इसे दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को और गहरा करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2001 से जारी है ऊर्जा साझेदारी भारत और मॉरीशस की ऊर्जा साझेदारी नई नहीं है। वर्ष 2001 में इंडियन ऑयल ने इंडियन ऑयल मॉरीशस लिमिटेड के माध्यम से मॉरीशस में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। नया समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देता है।

पुरी और मॉरीशस के वाणिज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जॉन माइकल त्जून साओ युंग सिक युएन के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। 5 हजार किमी दूर, फिर भी भारत के लिए बेहद खास भौगोलिक दूरी भले ही करीब 5,000 किलोमीटर हो, लेकिन भारत और मॉरीशस के रिश्ते इतिहास, संस्कृति और रणनीतिक हितों से गहराई से जुड़े हैं। 1834 के बाद बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक मॉरीशस पहुंचे और दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर मजबूत संबंध बने। मॉरीशस की स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1968 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। मॉरीशस की करीब 70 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की बताई जाती है। हिंदी और भोजपुरी के साथ दीपावली और महाशिवरात्रि जैसे भारतीय त्योहार वहां सामाजिक-सांस्कृतिक जुड़ाव की मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। हिंद महासागर में रणनीतिक ताकत मॉरीशस की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

दिल्ली को मिलेंगी 200 नई ई-बसें, रफ्तार पकड़ेगी हरित सवारी

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। बुधवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के फ्लैग-ऑफ के साथ दिल्ली के ई-बस बेड़े के करीब 5,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलने की संभावना है। महिलाओं के लिए लेडीज स्पेशल बस सेवा ई-बसों के विस्तार के साथ दिल्ली में कई नई परिवहन सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। इनमें लेडीज स्पेशल बस सेवा प्रमुख है। इसका उद्देश्य महिला यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन में अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है।

दिल्ली-करनाल के बीच दौड़ेंगी ई-बसें

दिल्ली से करनाल के बीच इंटरस्टेट

इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इसके जरिए दोनों शहरों के बीच पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मजबूत होगा। यात्रियों को अंतरराज्यीय सफर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिल सकेगी। राजघाट डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ते इलेक्ट्रिक बस बेड़े की जरूरतों को देखते हुए राजघाट डिपो-कमें पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किया जाएगा। चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार ई-बसों के सुचारु संचालन के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने और पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने की दिशा में भी यह विस्तार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई ई-बसों, प्रस्तावित लेडीज स्पेशल सेवा, दिल्ली-करनाल इंटरस्टेट कनेक्टिविटी और चार्जिंग ढांचे के विस्तार से राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, हरित और यात्री-केंद्रित बनाने की कोशिश तेज होती दिखाई दे रही है।

पाक में मुनीर का दबदबा, तीनों सेनाओं की कमान एक हाथ में

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com

इस्लामाबाद, 21 अगस्त 2026। पाकिस्तान में सैन्य ढांचे में बड़े बदलाव के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत और बढ़ गई है। नए रक्षा कानून के तहत उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के रूप में थल सेना, नौसेना और वायु सेना की एकीकृत कमान सौंप दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की तीनों सशस्त्र सेनाएं एक केंद्रीय कमान व्यवस्था के तहत आ गई हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का पद खत्म पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026 और नेशनल कमान अथॉरिटी एक्ट, 2010 में संशोधनों को मंजूरी दी है। नए ढांचे में पूर्ववर्ती चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पद को समाप्त कर CDF का पद बनाया गया है। वर्तमान में यह जिम्मेदारी आसिम मुनीर के पास है। नए कानून के तहत डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर

(DFHQ) स्थापित करने का प्रावधान है। यह तीनों सेनाओं के केंद्रीय मुख्यालय के रूप में काम करेगा और इसकी कमान CDF के पास होगी। ऑपरेशन से लेकर प्रशासन तक व्यापक अधिकार

नए सैन्य ढांचे के तहत CDF को तीनों सेनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इनमें सैन्य अभियानों से संबंधित निर्णय, अभियान शुरू करने या रोकने, युद्धविराम और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सैन्य मामलों में समन्वय शामिल है। इसके अलावा सैन्य संसाधनों और रणनीतियों के एकीकरण में भी CDF की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक मामलों में भी उन्हें व्यापक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार होंगे CDF

नए प्रावधानों के तहत CDF पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेंगे। तीनों सेनाओं की कमान और नियंत्रण से जुड़े मामलों में उच्चसंघीय सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। कानून में भविष्य में CDF को अतिरिक्त जिम्मेदारियां और अधिकार सौंपने का प्रावधान भी रखा गया है। इसी वजह से पाकिस्तान की नई सैन्य व्यवस्था को सत्ता के केंद्रीकरण के नजरिए से भी देखा जा रहा है। परमाणु कमान के लिए अलग व्यवस्था

सैन्य पुनर्गठन के साथ पाकिस्तान ने रणनीतिक और परमाणु बलों के लिए भी नई कमान व्यवस्था तैयार की है। 27वें संविधान संशोधन के तहत कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (CNSC) का पद बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा को पदोन्नत कर देश का पहला CNSC नियुक्त किया गया है। यह पद पाकिस्तान के रणनीतिक और परमाणु बलों के परिचालन एकीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने बताया जरूरी संवैधानिक बदलाव पाकिस्तान सरकार ने संसद से पारित संशोधनों को नई संवैधानिक और सैन्य संरचना के अनुरूप जरूरी कदम बताया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुसार, बदलावों का उद्देश्य पाकिस्तान की परमाणु एवं रणनीतिक कमान व्यवस्था को नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप व्यवस्थित करना है। हालांकि, नए कानून के बाद आसिम मुनीर के हाथों में तीनों सेनाओं की कमान आने से पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था में सेना की भूमिका और अधिकारों को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।

अल नीनो का अलर्ट: रसोई पर मंडरा रहा महंगाई का संकट

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026। देश में खाद्य महंगाई को लेकर चिंता एक बार फिर गहराने लगी है। चीनी, सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच अब प्रशांत महासागर में मजबूत होता अल नीनो भारत के मानसून, कृषि उत्पादन और रसोई के बजट के लिए संभावित खतरे के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आने वाले महीनों में बारिश का वितरण प्रभावित हुआ तो फसलों की पैदावार घट सकती है, जिससे बाजार में सप्लाई कम होने और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका है। हालांकि फिलहाल सरकार का कहना है कि खरीफ फसल पर अल नीनो का बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है। मानसून पर टिकी महंगाई की दिशा

अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के सामान्य से अधिक गर्म होने की प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसका असर दुनिया भर में बारिश और तापमान के पैटर्न पर पड़ता है। भारत में यह अक्सर कमजोर या असमान मानसून से जुड़ा माना जाता है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। सब्जियां और चीनी सबसे ज्यादा संवेदनशील भारी बारिश से सप्लाई चेन बाधित होने और कुछ क्षेत्रों में कम बारिश के कारण टमाटर, प्याज, आलू व हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वहीं वैश्विक स्तर पर गन्ना उत्पादन प्रभावित होने की आशंका से चीनी बाजार पर भी नजर बनी हुई है। सरकार बोली–फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि इस वर्ष खरीफ उत्पादन पर अल नीनो का बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। अधिकांश राज्यों में फसलों की पानी की जरूरत पूरी करने लायक वर्षा हुई है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय चुनौतियां बनी हुई हैं। अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है असर यदि खाद्य महंगाई लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर केवल घरेलू बजट तक सीमित नहीं रहेगा। बढ़ती महंगाई उपभोक्ता मांग, खुदरा मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास की रफ्तार को भी प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में मानसून, खरीफ उत्पादन और मंडियों की सप्लाई पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। फिलहाल देश किसी बड़े खाद्य संकट की स्थिति में नहीं है, लेकिन मौसम का बदलता मिजाज संकेत दे रहा है कि आने वाले महीने किसानों, बाजार और आम उपभोक्ताओं–तीनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।

सोने की खदान बनी मौत का कुआं, 100 से ज्यादा खनिकों की मौत

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com

याम्बो, 21 अगस्त 2026। कैमरून-मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) सीमा के पास सोने की खदान ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। जाम्बोये गांव के पास हुए इस हादसे में 100 से अधिक खनिकों की मौत की खबर है। स्थानीय प्रशासन और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मलबे से अब तक 107 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि राहत एवं बचाव अभियान अभी जारी है। दोपहर में अचानक ढही खदान कैमरून के पूर्वी क्षेत्र के गवर्नर ग्रेगोयर म्वोंगो के अनुसार हादसा स्थानीय समयानुसार मंगलवार दोपहर करीब दो बजे हुआ। उन्होंने बताया कि जाम्बोये गांव सीमा क्षेत्र में स्थित है, जबकि हादसे वाली खदान मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमा में थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में तीन से पांच कैमरूनी नागरिक शामिल हैं। कैमरून के सरकारी प्रसारक सीआरटीवी ने मृतकों की संख्या 100 से अधिक बताई है। वहीं स्थानीय मीडिया के अनुसार बचाव दल ने अब तक 107 शव बरामद किए हैं।

मृतकों की संख्या पर अलग-अलग आंकड़े मध्य अफ्रीकी गणराज्य के खान एवं भूविज्ञान मंत्री रूफिन बेनाम-बेलटूंगू ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद 49 मौतों की पुष्टि की। उनके अनुसार मृतकों में 34 मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 13 कैमरून और दो चाड के नागरिक शामिल हैं। मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आने के बीच बचाव अभियान जारी है। आशंका है कि कई खनिक अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। खदान बंद करने का आदेश

मंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद खदान को बंद करने का आदेश दिया। कुछ खदान प्रबंधकों ने हादसे के संभावित कारणों में खनिकों की अनुशासनहीनता का भी उल्लेख किया है। प्रशासन की ओर से हादसे की परिस्थितियों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। परिवारों में पसरा मातम हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासी ओरिएजीन डॉकना ने बताया कि मंगलवार से ही कई परिवार अपने प्रियजनों के शोक में डूबे हैं। बचावकर्मी मलबे को हटाकर संभावित रूप से फंसे खनिकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अफ्रीका में खदान सुरक्षा पर फिर सवाल अफ्रीका में हाल के वर्षों में सोने की खदानों में दुर्घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले महीने केन्या के नारोक काउंटी में भी सोने की खदान ढहने से पांच खनिकों की मौत हुई थी। ताजा हादसे ने खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।

महाराष्ट्र में दर्दनाक घटना, बेटे को बचाने की कोशिश में माता-पिता की भी मौत

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। शुरू आती जानकारी के मुताबिक, परिवार का 18 वर्षीय बेटा पहाड़ी क्षेत्र में गंभीर संकट की स्थिति में था। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे काफी देर तक समझाने और सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति को संभाला नहीं जा सका। बेटे को बचाने के प्रयास में उसके पिता की भी जान चली गई और इसके बाद मां की भी मृत्यु हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, परिवार देवलाई इलाके का रहने वाला था। शुक्रवार सुबह परिवार के सदस्य पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां युवक बेहद परेशान नजर आ रहा था। परिजनों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी उससे बातचीत कर उसे शांत करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि करीब तीन घंटे तक लोग युवक को समझाते रहे। उसे अपने भविष्य और परिवार के बारे में सोचने के लिए कहा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्थिति को नियंत्रित करने और युवक को सुरक्षित स्थान पर लाने का प्रयास किया। काफी देर तक समझाने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक को सुरक्षित करने के प्रयास में उसके पिता भी उसके पास पहुंचे।

ओडिशा में बाढ़ का कहर थमा, 6 जिलों में हालात सुधरे, खतरे के निशान से नीचे नदियां, बारिश भी थमी

भुवनेश्वर/बालासोर (एजेंसी)। ओडिशा के छह जिलों में शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ और पिछले 48 घंटों में भारी बारिश नहीं होने से सबसे अधिक प्रभावित बालासोर जिले की सुवर्णरेखा समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। अधिकारियों ने बताया कि सुवर्णरेखा की बाढ़ से बालियापाल, भोगराई और जलेश्वर प्रखंड जलमग्न हो गए थे और करीब 2.1 लाख लोग प्रभावित हुए। राजघाट में नदी का जलस्तर 9.75 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। 20 अगस्त को जलस्तर 11.82 मीटर तक पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि बालियापाल

में करीब एक लाख, भोगराई में 70 हजार और जलेश्वर में 40 हजार लोग प्रभावित हुए। जालका और बुधबलंगा नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे आ गया है, हालांकि जिले के करीब 100 गांव अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। अधिकारियों के अनुसार, 14 अगस्त से शुरू हुई बाढ़ की दूसरी लहर से छह जिलों में 13 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और करीब पांच लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, केंद्रापड़ा, मयूरभंज और क्योंझर में स्थिति स्थिर है, हालांकि बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ने से केंद्रापड़ा और जाजपुर के कुछ हिस्सों में खतरा बना हुआ है।

सीएम धामी की घोषणा; स्वयं सहायता समूहों के लिए 13 गांव में खोले जाएंगे विपणन केंद्र

देहरादून (एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल-2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के सभी जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला, युवा और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। वहीं, 8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता एवं आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के गांव अब प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं में हुनर एवं कुछ नया करने का जज्बा है, जबकि स्थानीय उत्पादों में देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। सरकार का उद्देश्य इस हुनर को सही दिशा और बाजार उपलब्ध कराना है।

संपादकीय

पीएम केयर्स फंड का ऑडिट

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मार्च 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद श्पीएम केयर्सश नाम का प्रचार-प्रसार वाला शब्द गढ़ा था, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वह लोगों का ध्यान रखते हैं। इस शब्दावली को विस्तारित कर इसका नाम रखा गया श्प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन एसिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशनश (आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत) रखा गया और इसे 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया, ठीक 24 मार्च 2020 की शाम को लॉकडाउन की घोषणा के बाद। विपक्ष का आरोप था कि इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग इसलिए बनाया गया था ताकि फंड की सार्वजनिक जांच से बचा जा सके। अब छह साल बाद हमें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय दान का पैसा बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना ज्यादा पसंद था। इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब 2024-25 के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक किया गया। ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान पीएम केयर्स फंड को कुल 1279.9 करोड़ रुपये मिले, लेकिन उसने केवल 87.85 लाख रुपये खर्च किए। पीएम केयर्स फंड के पास कुल 8,542 करोड़ रुपये उपलब्ध थे, जिसमें से 7,847 करोड़ रुपये (लगभग 93 प्रतिशत) बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए थे, जबकि 605 करोड़ रुपये सेविंग्स अकाउंट में रखे गए थे। यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को दशार्ता है, जिन्होंने देश के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही लगती है। जब से पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई, यह मुख्य रूप से एक ट्रस्ट के तहत निजी फंड के रूप में स्थापित होने के कारण विवादों में रहा, हालांकि इसमें राष्ट्रीय प्रतीक श्सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभश का इस्तेमाल किया गया था, जिसके आधार पर श्सत्यमेव जयतेश लिखा था और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी शामिल था। ऐसा स्पष्ट रूप से कैग ऑडिट से बचने और आरटीआई अधिनियम के तहत जनता को जानकारी देने से रोकने के लिए किया गया था। इसे एक सरकारी संस्था के तौर पर नहीं बनाया गया था, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर दान मांगा और लिया गया था। जमा किए गए फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और फंड के ट्रस्टी अपनी मर्जी से करते हैं, और यह भारत सरकार के खातों का हिस्सा नहीं होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय नियमित रूप से मिले फंड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं देता है। शुरूआती सालों से लेकर 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट बहुत देरी से जारी की गईं, और दो साल के अंतराल के बाद, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के ऑडिट किए गए स्टेटमेंट 18 अगस्त, 2026 को सार्वजनिक किए गए। यह फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है, और 2022-23 के दो वर्ष बाद भी पब्लिक ऑडिट स्टेटमेंट न होने के कारण इसे जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचनाओं में से एक यह थी कि जो फंड जनता का पैसा स्वीकार करता है- जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योगदान और दूसरों से दान शामिल है - उसे पब्लिक ऑडिट के दायरे से बाहर क्यों रखा जाए, जबकि इस निजी फंड को एक सरकारी संस्था जैसा दिखाया जाता है। आलोचकों का तर्क था कि यह बेईमानी थी। एक और विवाद प्रधानमंत्री के इस फंड के चेयरमैन (पदेन हैसियत से) होने और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के इसके ट्रस्टी होने से जुड़ा था। पीएम केयर्स ने हमेशा यही रुख अपनाया और आरटीआई आवेदकों को जानकारी देने से इनकार किया, यह कहते हुए कि ट्रस्ट आरटीआई एक्ट के तहत कोई सरकारी संस्था नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल दान लेने के लिए किया गया, जिसके लिए कानूनों में भी बदलाव किए गए- जैसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के नियमों में- और वह भी पिछली तारीख से लागू होने वाले बदलाव। इसकी आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि इसकी गतिविधियां जनता के प्रति जवाबदेही से परे थीं, और ये पूरी तरह से इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी (चाहे वह सही हो या गलत) पर निर्भर थीं। 2020-21 में पीएम केयर्स की कुल आय 7,913.5 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसने केवल 3,976.2 करोड़ रुपये खर्च किए। 2021-22 में फंड को 2,116.2 करोड़ रुपये मिले और उसने 3,716.3 करोड़ रुपये खर्च किए। 2022-23 में इसे 1,305.9 करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ 437.9 करोड़ रुपये खर्च किएय 2023-24 में इसे 904.9 करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ 15.6 करोड़ रुपये खर्च किएय और 2024-25 में इसे 1,279.9 करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ 0.9 करोड़ रुपये खर्च किए। कुल मिलाकर, मार्च 2020 में शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2025 तक, इस फंड ने अपनी कुल कमाई का पांचवें हिस्से से भी कम- यानी सिर्फ 18.4 प्रतिशत - खर्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसने अपने क्लोजिंग फंड का सिर्फ 0.01 प्रतिशत खर्च किया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि फंड का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक और इंसानी आपदाओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में जरूरतमंदों की मदद के नाम पर मिले फंड का 93 प्रतिशत बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा करना नैतिक या मानवीय रूप से सही नहीं लगता।

छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया

> मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और रैलियां निकाली हैं। कहीं बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी, तो कहीं होस्टल की ज्यादा फीस जैसे मुद्दों ने छात्रों को सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। बदलाव और बेचैनी की ऊर्जा से भरी यह हलचल हमारे समाज, राजनीति और सरकारी तंत्र को वर्तमान दौर की चुनौतियों को समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देती है। इन आंदोलनों ने कुछ अहम पहलुओं को रेखांकित किया है। कुछ नए ट्रेंड उभर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। आमतौर पर किसी मुद्दे, मांग या विषय के पक्ष-विपक्ष में जनता के विभिन्न वर्ग बड़े शहरों में एकजुट होते आए हैं।

राजेश पांडेय

20 जून को जंतर-मंतर, नई दिल्ली से शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की आवाज देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और रैलियां निकाली हैं। कहीं बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी, तो कहीं होस्टल की ज्यादा फीस जैसे मुद्दों ने छात्रों को सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। बदलाव और बेचैनी की ऊर्जा से भरी यह हलचल हमारे समाज, राजनीति और सरकारी तंत्र को वर्तमान दौर की चुनौतियों को समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देती है। इन आंदोलनों ने कुछ अहम पहलुओं को रेखांकित किया है। कुछ नए ट्रेंड उभर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। आमतौर पर किसी मुद्दे, मांग या विषय के पक्ष-विपक्ष में जनता के विभिन्न वर्ग बड़े शहरों में एकजुट होते आए हैं। अक्सर राजनीतिक दलों, छात्रों, मजदूर संघों और सामाजिक संगठनों द्वारा जनमत जगाने, विरोध जताने और लोगों को संगठित करने की मुहिम राजधानियों या बड़े शहरों में आकार लेती है। बहुत व्यापक आंदोलनों को छोड़ दें तो कई बार वह उन्हीं स्थानों तक सिमटकर रह जाती है। इस बार स्थिति अलग है। दिल्ली, भोपाल, रायपुर जैसी राजधानियों से उठी आवाज की अनुगूंज छोटे शहरों में सुनाई पड़ रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों के स्वरूप में हुआ है। कॉलेज छात्रों के साथ स्कूली छात्र आगे आए हैं। स्कूली छात्र सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित नहीं हैं। कई जगह मिडिल स्कूल के छात्रों ने सीनियर साथियों के साथ मोर्चा संभाला है। लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। वे सिर्फ दिल्ली या राजधानियों में ही नहीं छोटे शहरों तक में सड़क पर उतरी हैं। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर है, वे मौजूदा स्थितियों में अपने भविष्य के प्रति

आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें जिंदगी की दौड़ में पिछड़ने का खतरा नजर आता होगा। छोटे शहरों के छात्रों के जागरूक होने का मुख्य कारण उनकी मांग तो है ही पर सोशल मीडिया ने उनके लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मोबाइल के परदे का छोटा स्क्रीन उन्हें दिल्ली से लेकर सैनफ्रांसिस्को तक की हलचल की जानकारी देता है। वे सिर्फ रील बनाने, देखने या मनोरंजन तक सीमित नहीं होंगे। उन्हें साइंस, टेक्नालॉजी, इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। स्पेस साइंस के चमत्कार भी उनकी कल्पनाओं का हिस्सा बन रहे होंगे। वे देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के कोई मार्क जकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा टूल बनाते हैं तो कैसे ओपन एआई के सैम आल्टमैन चौट जीपीटी पेश कर रहे हैं। वे यह भी जानने लगे हैं किस तरह मेडिकल साइंस ने दिल और मस्तिष्क के रोगों सहित कई लाइलाज बीमारियों में राहत देने का रास्ता खोज लिया है। सूचना क्रांति का वर्तमान समय छात्रों सहित हर किसी को लोकतंत्र, आजादी और खुलेपन की अहमियत बताता है। वह उनके अंदर सिस्टम की जड़ता को तोड़ने और नई राह पर चलने की बेचैनी पैदा करता है। उन्हें कहीं लगता है कि वे असली बदलाव से बहुत दूर हैं। युवा महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था उन्हें सिर्फ प्रतियोगिता की अंतहीन होड़ में झोंक रही है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को नैतिकता, ईमानदारी, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्यों के प्रसार का वाहक होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। हम हर कहीं मूल्यों का क्षरण देखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है। ऐसे सिस्टम से युवाओं का मोहभंग और हताशा स्वाभाविक है। आधुनिक दौर में ऐसी व्यवस्था के खिलाफ ताकतवर स्वर उभरते रहे हैं। युवाओं और आम लोगों ने समय-समय पर सत्ता को झकझोरने के लिए अपना असंतोष जाहिर किया है। छात्रों के सत्याग्रह का जिक्र होता है तो मार्च, मई 1968 में फ्रांस के छात्र आंदोलन को हमेशा याद किया जाता है। उस वक्त पेरिस में छात्रों ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्रों की भीड़, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त साधनों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। देश की ट्रेड यूनियन भी छात्रों के साथ खड़ी हो गई थीं। आंदोलन दूसरे शहरों में फैल गया। मजदूर संघों के साथ आने से कारखानों, दफ्तरों में काम ठप पड़ गया था। फ्रांस के आंदोलन में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल की दस साल लंबी सत्ता का विरोध भी जुड़ा था। डिगाल का शासन अनुदारवादी था। उनकी तानाशाही और मनमानी के खिलाफ नौजवानों और मजदूर वर्ग में असंतोष पनप रहा था। डिगाल ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने नेशनल असेम्बली भंग कर दी। नए चुनाव कराए। देश में फैली अस्थिरता से परेशान मध्यम वर्ग ने डिगाल का समर्थन किया। उनकी पार्टी को संसद में फिर बहुमत मिल गया। 1969 में डिगाल ने संसद के स्वरूप में बदलाव के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया। लेकिन जनमतसंग्रह में हारने पर अप्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में विभिन्न स्तरों पर चल रही छात्रों की हलचल का संबंध व्यवस्था विरोधी भी है। निश्चित रूप से वह स्कूल, कॉलेजों में साधनों के अभाव से जुड़ा है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.8 से 4.3 प्रतिशत के बीच चल रहा है। वैसे, राष्ट्रीय नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की नीति रही है। लेकिन सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा राज्यों का विषय है। इसलिए राज्यों के हिस्से में शिक्षा के खर्च का हिस्सा 75 प्रतिशत और केंद्र सरकार का 25 प्रतिशत है। शिक्षा की पहली सीढ़ी स्कूल हैं। इसलिए उसके खर्च में कमी का असर भविष्य में शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर पर पड़ता है। अपर्याप्त बजट का नतीजा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शाला भवनों की दुर्दशा और अन्य सुविधाओं के अभाव में सामने आया है। विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के स्कूल ज्यादा अभावग्रस्त हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उपेक्षा को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं। देश में 2014-15 से 2024-25 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 94 हजार कम हुई है। इसमें उन स्कूलों की संख्या शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारें किसी अन्य स्कूल में शामिल करती हैं। अच्छी बात यह है कि इस दरम्यान शिक्षकों की संख्या में 11 लाख से अधिक इजाफा हुआ है। इन स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या दो करोड़ 26 लाख कम हो गई थी। सरकारी स्कूलों की घटती संख्या और साधनों का अभाव शिक्षा के प्रति सरकारों की प्राथमिकता का प्रमाण है। रोजगार के नए अवसरों के सृजन और भावी चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने के मामले में भी सरकारी तंत्र की भूमिका कारगर नहीं है। भारत में शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से है। असंतोष और संकट के मूल में बढ़ती बेरोजगारी है।

हेल्थकेयर की चुनौतियां

> नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2025 के सर्वे का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने पाया है कि सरकारी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का औसत खर्च 6,631 रुपये है, जबकि प्राइवेट में यह खर्च 50,508 रुपये है। निजी अस्पताल में होने वाला यह औसत खर्च सरकारी अस्पताल में होने वाले खर्च के मुकाबले सात गुना से भी अधिक है। जो चिकित्सा सुविधाओं में व्याप्त व्यापक विसंगतियों को ही दशार्ता है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है कि निजी अस्पताल अब साठ फीसदी से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करते हैं और 70 फीसदी आउट पेशेंट की देखभाल करते हैं। विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव लगातार बना रहता है। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मरीज महसूस करते हैं। सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में बेड, उपकरण, दवाइयां और कुशल स्टाफ की कमी देखी जाती है। मरीज को भरोसा नहीं होता है कि उसे जरूरी इलाज सरकारी अस्पताल में मिल भी पायेगा। एक संकट यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की अच्छी आय और निजी प्रैक्टिस का सम्मोहन भी योग्य डाक्टरों को सरकारी अस्पतालों से विमुख बनाता है। यही वजह है कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

यह विडंबना ही है कि देश में कभी भी सत्ताधीशों की प्राथमिकता सरकारी चिकित्सा-तंत्र को सक्षम बनाने की नहीं रही है। किसी भी चुनाव में स्वास्थ्य सुविधाओं को समृद्ध बनाना राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं रहा। जनता भी हर आम परिवार से जुड़े सेहत के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने में चूकती रही है। यही वजह है कि आज भी कुल मिलाकर देश के करोड़ों लोगों के लिये सस्ती व पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच से बाहर हैं। अपने परिजनों के गंभीर रोगों के उपचार के लिये क्षमता से अधिक पैसा जुटाने के फेर में हजारों परिवार हर साल गरीबी की दलदल में धंस जाते हैं। यह गंभीर स्थिति सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थकेयर पर बनी संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर दशार्ती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2025 के सर्वे का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने पाया है कि सरकारी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का औसत खर्च 6,631 रुपये है, जबकि प्राइवेट में यह खर्च 50,508 रुपये है। निजी अस्पताल में होने वाला यह औसत खर्च सरकारी अस्पताल में होने वाले खर्च के मुकाबले सात गुना से भी अधिक है। जो चिकित्सा सुविधाओं में व्याप्त व्यापक विसंगतियों को ही दशार्ता है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है कि निजी अस्पताल अब साठ फीसदी से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करते हैं और 70 फीसदी आउट पेशेंट की देखभाल करते हैं। विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव लगातार बना रहता है। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मरीज महसूस करते हैं। सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में बेड, उपकरण, दवाइयां और कुशल स्टाफ की कमी देखी जाती है। मरीज को भरोसा नहीं होता है कि उसे जरूरी इलाज सरकारी अस्पताल में मिल भी पायेगा। एक संकट यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की अच्छी आय और निजी प्रैक्टिस का सम्मोहन भी योग्य डाक्टरों को सरकारी अस्पतालों से विमुख बनाता है। यही वजह है कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिये बाध्य होना पड़ता है। दरअसल, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, अब चाहे उनकी पैसा देने की क्षमता हो या न हो। लोगों की चिकित्सा इमरजेंसी की चिंता की वजह से स्वास्थ्य बीमा का बड़ा कारोबार देश में फल-फूल रहा है। जिसमें मरीजों को कम व बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। यही वजह है कि आज हेल्थकेयर सिस्टम में इलाज की सुविधा परिवार की आमदनी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है। इसके चलते ही संसदीय पैनल की यह बात खास तौर पर चिंताजनक है कि अस्पताल में भर्ती होने का औसत बिल 37,858 है, जिसमें से मरीज अपनी जेब से लगभग 34,064 रुपये खर्च करते हैं। हालांकि, कुल बिल में अपनी जेब से होने वाला खर्च 2014 के 62.6 फीसदी से घटकर 2022-23 में 43.4 फीसदी हो गया है। इसके बावजूद 10-13 फीसदी की मेडिकल महंगाई का असर परिवारों के बजट पर अब भी पड़ रहा है। लेकिन सरकारी सुविधाओं में आ रही गिरावट को टाला न जा सकने वाला मान लेना भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शासन-प्रशासन की प्राथमिकता सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की होनी चाहिए। निस्संदेह, संसदीय समिति की सिफारिशें सही दिशा की ओर संकेत देती हैं। इसमें छोटे और ग्रामीण अस्पतालों के लिये लक्षित सहायता, पारदर्शी इलाज पैकेज, बीमा दरों की समय-समय पर समीक्षा, मध्यम आय वाले वर्ग के लिये किफायती बीमा सुविधा, जेनेरिक दवाइयों तक मरीजों की व्यापक पहुंच बनाने तथा शहरों से परे मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है। सही मायने में देश की स्वास्थ्य सेवा संबंधी महत्वाकांक्षाओं को केवल उसके चिकित्सा बाजार के आकार से नहीं मापा जाना चाहिए। साल 2030 तक 202.5 अरब डॉलर तक पहुंचने के अनुमानित क्षेत्र को यह भी साबित करना होगा कि देश में लाखों परिवारों को कर्ज की दलदल में धकेले बिना भी गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध है।

वृद्धाश्रम नहीं, अब चाहिए वृद्ध सुविधाश्रम

संपादकीय` भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बुजुर्ग किसी भी परिवार की जड़ और समाज की जीवंत विरासत होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को संवारने, बच्चों को आगे बढ़ाने और समाज को मजबूत बनाने में लगा दी। इसलिए वृद्धावस्था में उन्हें केवल आश्रय नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आत्मीयता और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे समाज में वृद्धाश्रम शब्द सुनते ही मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है, जिसमें बुजुर्ग अपने परिवार से दूर और उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। इस नकारात्मक धारणा के कारण परिवार भी वृद्धाश्रम का नाम लेने से संकोच करते हैं। लेकिन बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने अब हमें इस विषय पर भावनाओं के साथ-साथ व्यावहारिक दृष्टि से भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज गांवों में ऐसे अनेक वृद्धजन हैं जो अकेले रह रहे हैं। कहीं परिवार में केवल एक संतान है, कहीं बेटा रोजगार के लिए दूसरे शहर या राज्य में चला गया है, तो कहीं आर्थिक परिस्थितियां पति-पत्नी को अलग-अलग स्थानों पर रहने के लिए विवश करती हैं। परिणाम यह है कि उम्र के उस पड़ाव पर, जब व्यक्ति को सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है, वह कई बार अपने घर में भी अकेला पड़ जाता है। स्थिति तब और कठिन हो जाती है जब वृद्धजन शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो जाएं कि खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना या दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए कठिन हो जाए। ऐसे में केवल यह कहना कि बेटा-बहू साथ रहेंगे वास्तविक समस्या का समाधान नहीं है।

बहू को ही वृद्ध माता-पिता की पूरी जिम्मेदारी सौंप देना भी हमेशा व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। विशेषकर तब, जब बेटा लंबे समय तक रोजगार के लिए बाहर रहता हो। बहू की अपनी सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए समस्या को किसी एक व्यक्ति के कंधे पर डालने के बजाय सामूहिक और व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता है। यहीं से वृद्ध सुविधाश्रम की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। वृद्ध सुविधाश्रम क्यों? वृद्ध सुविधाश्रम को पारंपरिक वृद्धाश्रम की तरह नहीं, बल्कि सम्मानजनक वरिष्ठ नागरिक जीवन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। 75 वर्ष से अधिक आयु के उन बुजुर्गों के लिए, जिन्हें घर पर पर्याप्त देखभाल, सुरक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, यह व्यवस्था एक बेहतर विकल्प बन सकती है। यहां केवल रहने के लिए कमरा और दो वक्त का भोजन पर्याप्त नहीं होना चाहिए। पौष्टिक भोजन, चाय-पानी, स्वच्छता, कपड़े धोने की सुविधा, 24 घंटे सहायता, प्राथमिक चिकित्सा, नियमित स्वास्थ्य जांच, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हों।

इसके साथ-साथ जीवन में आनंद भी होना चाहिए। हमउम्र साथियों के साथ बातचीत, मनोरंजन, पुस्तकालय, धार्मिक गतिविधियां, योग-ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक यात्राएं बुजुर्गों के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती हैं। क्यों न ऐसे केंद्रों से धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं आयोजित हों? क्यों न बुजुर्ग सामाजिक समारोहों और पारिवारिक आयोजनों में सम्मान के साथ भाग लें? आखिर उम्र बढ़ने का अर्थ सामाजिक जीवन समाप्त हो जाना तो नहीं है। परिवार का विकल्प नहीं, सहयोगी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्ध सुविधाश्रम को परिवार से मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि परिवार की सहयोगी व्यवस्था बनाया जाए। यदि बेटा-बहू अपनी कर्मभूमि पर रहने के लिए मजबूर हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अपने माता-पिता को छोड़ दिया। परिवार नियमित रूप से उनसे मिले, आर्थिक जिम्मेदारी उठाए, स्वास्थ्य की जानकारी रखे और समय-समय पर उन्हें अपने साथ भी रखे। वृद्ध सुविधाश्रम और परिवार के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए, जिसमें बुजुर्ग स्वयं को परिवार से अलग नहीं, बल्कि परिवार और समाज दोनों का हिस्सा महसूस करें।

सुरक्षा भी बड़ी चुनौती आज अकेले रहने वाले वृद्धजनों की सुरक्षा भी गंभीर विषय है। चोरी, लूट और अन्य अपराधों में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक कई बार आसान लक्ष्य बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित और निगरानीयुक्त आवासीय व्यवस्था उनके लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है। हमें भविष्य की सामाजिक वास्तविकताओं को समझना होगा। केवल इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, ऐसी व्यवस्था से आंखें मूंद लेना समाधान नहीं है। आधुनिक समाज का अर्थ केवल आधुनिक जीवनशैली नहीं, बल्कि समस्याओं के आधुनिक और मानवीय समाधान तलाशना भी है। गांव से तहसील और धार्मिक स्थलों तक वृद्ध सुविधाश्रम की शुरूआत गांवों से हो सकती है। जहां हर गांव में संभव न हो, वहां तहसील स्तर पर सामुदायिक वृद्ध सुविधाश्रम विकसित किए जा सकते हैं। प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के आसपास भी ऐसे केंद्र विकसित किए जाएं, जहां बुजुर्गों को शांत, आध्यात्मिक और सुरक्षित वातावरण मिल सके।

इन केंद्रों का संचालन सरकार, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और समाज के सहयोग से किया जा सकता है। लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वृद्धजन किसी पर उपकार के बोझ तले दबे महसूस न करें। उनकी देखभाल दया नहीं, उनका अधिकार और परिवार की जिम्मेदारी है। इसलिए जहां संभव हो, वृद्धजन की पूरी देखभाल का खर्च उनके परिवार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। समाज और संस्थाएं व्यवस्था उपलब्ध कराने में सहयोग करें, लेकिन बुजुर्गों को यह महसूस न कराया जाए कि वे किसी पर बोझ हैं। भगवान, अब तो उठा लो न सुनना पड़े हमारे समाज के लिए इससे अधिक पीड़ादायक स्थिति क्या होगी कि जीवनभर परिवार के लिए संघर्ष करने वाला कोई वृद्ध अंत में असहाय होकर कहे-भगवान, अब तो उठा लो। यह केवल एक वृद्ध की पीड़ा नहीं है। यह पूरे समाज के सामने खड़ा प्रश्न है।

क्या हमने अपने बुजुर्गों को केवल जीवित रखने की व्यवस्था की है, या उन्हें जीने का अधिकार भी दिया है? बुढ़ापा बीमारी, अकेलेपन और उपेक्षा का पर्याय नहीं होना चाहिए। यह जीवन का वह पड़ाव हो सकता है जहां व्यक्ति अपने अनुभव साझा करे, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले, मित्रों के साथ समय बिताए और अपने जीवन की यात्रा को संतोष के साथ देखे। सोच बदलने का समय अब समय आ गया है कि हम वृद्धाश्रम शब्द से जुड़ी नकारात्मक सोच पर पुनर्विचार करें। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें वृद्धजन परिवार से दूर होने के बावजूद परिवार से कटे हुए न हों।

वृद्ध सुविधाश्रम का उद्देश्य माता-पिता से जिम्मेदारी छुड़ाना नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने में परिवार की सहायता करना होना चाहिए। जिस मां-बाप ने अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर बच्चों का भविष्य बनाया, उनके जीवन की संध्या सुखद बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्हें अच्छा भोजन मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, मित्रों का साथ मिले, धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले और सबसे बढ़कर-उन्हें सम्मान मिले। हमें हर गांव में ऐसी व्यवस्था की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। यदि हर गांव में संभव न हो तो तहसील स्तर पर और आवश्यकता हो तो जिला या प्रमुख धार्मिक केंद्रों के आसपास आधुनिक वृद्ध सुविधाश्रम विकसित किए जाएं। लेकिन एक बात हमेशा स्पष्ट रहनी चाहिए-वृद्ध सुविधाश्रम परिवार का विकल्प नहीं है। यह परिवार, समाज और व्यवस्था के बीच सहयोग का माध्यम है। बुजुर्गों को केवल सांसें देना पर्याप्त नहीं। उन्हें सुखी, सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वाभिमानपूर्ण जीवन देना ही सच्चे अर्थों में हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। शायद अब समय आ गया है कि हम वृद्धाश्रम की पुरानी छवि से आगे बढ़कर एक ऐसी नई व्यवस्था की कल्पना करें, जहां बुजुर्ग स्वयं कह सकें-

यह मेरा आश्रय नहीं, मेरा अपना घर है।

-सांवलराम चौधरी असाडा
एडिटर इन चीफ, पटेल टीवी
जोधपुर (राजस्थान)

आभार को हृदय में उतारें, मिलेगा मन का सुकून : मुनि वीरसागर

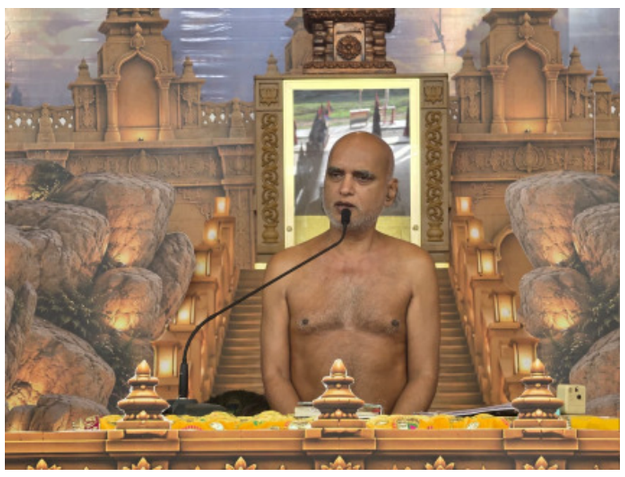

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 21 अगस्त 2026। निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीरसागर जी महाराज ने प्रेरणादायी प्रवचन में जीवन में आभार के भाव को जागृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य सुख और शांति की तलाश अक्सर बाहरी परिस्थितियों में करता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन उसके अपने विचारों, दृष्टिकोण और भावनाओं से शुरू होता है। जीवन में मिले उपकारों को पहचानकर उनके प्रति कृतज्ञ होना सीख लिया जाए तो संतोष, प्रसन्नता और मानसिक शांति का विकास सहज होने लगता है। मुनि श्री ने प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कई बार मनुष्य स्वयं ही अपने मानसिक बंधनों का निर्माण करता है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और उसी में फंस जाती है, रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर कोकून बनाकर उसमें बंध जाता है तथा हिरण के लिए सुंदरता का प्रतीक उसके सींग ही कई बार झाड़ियों और लताओं में उलझकर संकट का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपनी अपेक्षाओं, चिंताओं, स्मृतियों और नकारात्मक विचारों का जाल स्वयं बुनकर उसमें उलझ जाता है। उन्होंने कहा कि बाहरी घटना कुछ क्षणों में समाप्त हो जाती है, लेकिन मनुष्य उसे बार-बार स्मरण करके उसी पीड़ा को अनेक बार अनुभव करता रहता है। किसी के अपमान, अस्वीकार, अपेक्षा के विपरीत व्यवहार अथवा प्रतिकूल परिस्थिति को मन में पकड़े रखना सामने वाले को नहीं, बल्कि स्वयं के मन को अशांत करता है।

बहते जल की तरह रखें मन को गतिशील मुनि श्री ने बहते हुए जल का उदाहरण देते हुए कहा कि निरंतर गतिशील पानी निर्मल बना रहता है, जबकि ठहरा हुआ पानी धीरे-धीरे दूषित हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी पुराने दुःख, शिकायत, क्रोध और कटु स्मृतियों को मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। भावनाओं को गतिशील रहने देने से मानसिक वातावरण स्वस्थ और संतुलित बना रहता है। उन्होंने कहा कि इस मानसिक बोझ से मुक्त होने का प्रभावशाली उपाय आभार है। आभार केवल किसी व्यक्ति के उपकार के लिए धन्यवाद देना नहीं, बल्कि जीवन में प्राप्त प्रत्येक छोटे-बड़े सहयोग, सुविधा और अवसर को पहचानने की आंतरिक दृष्टि है। माता-पिता, गुरु और समाज के प्रति कृतज्ञता

मुनि श्री ने कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में योगदान देने वाले उपकारीजनों को पहचानना चाहिए। माता-पिता ने जीवन दिया, परिवार ने संरक्षण दिया, शिक्षक ने ज्ञान दिया, गुरु ने सही दिशा दिखाई और समाज ने अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई। इनके प्रति आभार का भाव मनुष्य में विनम्रता और संवेदनशीलता का विकास करता है। उन्होंने आभार की भावना को केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रखने की प्रेरणा दी। वायु जीवन देती है, जल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भूमि आधार देती है, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा देता है तथा प्रकृति बिना किसी अपेक्षा के निरंतर मानव जीवन का पोषण करती है। प्रकृति के इन उपकारों को अनुभव करने से जीवन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव गहरा होता है।

अपने शरीर और मन के प्रति भी रखें आभार मुनि श्री ने स्वयं के प्रति आभार रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर, मन और इंद्रियों का उपयोग तो करता है, लेकिन अक्सर इनके प्रति सजग नहीं रहता। असंयमित जीवनशैली, इंद्रियों का अनुचित उपयोग और मन को लगातार चिंता, ईर्ष्या तथा नकारात्मक विचारों में उलझाए रखना स्वयं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि शरीर के प्रति आभार का अर्थ केवल स्वस्थ होने पर प्रसन्न होना नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करना भी है। इसी शरीर के माध्यम से धर्म, सेवा, अध्ययन और श्रेष्ठ कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार मन भी एक महत्वपूर्ण साधन है। उसे लगातार भय, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मकता में उलझाए रखना उसकी शक्ति का अपव्यय है।

अभ्यास से स्वभाव बनेगा आभार मुनि श्री ने कहा कि हर व्यक्ति में आभार की भावना प्रारंभ से समान रूप से विकसित नहीं होती। परिस्थितियों के कारण कई बार शिकायत की प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है। ऐसे में आभार का अभ्यास आवश्यक है। शुरूआत में भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न न हो, तब भी जीवन में प्राप्त अच्छाइयों को देखना, स्वीकार करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास से मन की दिशा बदलने लगती है। जैसे बार-बार किए गए कार्य से आदत बनती है, वैसे ही सकारात्मक भावों का निरंतर चिंतन नई संस्कारधारा विकसित करता है। धीरे-धीरे आभार प्रयास का विषय न रहकर व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। मानसिक ऊ

युवा शक्ति को सही दिशा मिले तो देश नई ऊंचाई छुएगा

भारतार्थ खबर। संवाददाताः धन्नाराम चौधरी
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 21 अगस्त 2026। बेंगलुरु के चामराजपेट स्थित आदर्श महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में युवा एवं राष्ट्रीयता विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदर्श महाविद्यालय एवं राजस्थान पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में 20 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, संस्कार और

सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति और गति हैं। उन्होंने कहा कि कई युवा अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने अथवा डिग्री प्राप्त करने के बाद रोजगार नहीं मिलने से निराश हो जाते हैं। ऐसे युवाओं को निराश होने के बजाय दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है।

आदर्श महाविद्यालय के अध्यक्ष पदमराज मेहता ने कहा कि युवा भारत के कर्णधार हैं और देश की प्रगति की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उन्होंने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण कर जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। शिक्षा और संस्कारों से सशक्त युवा ही राष्ट्र को मजबूत दिशा दे सकते हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए निबंध, कविता, गीत, भाषण और लघु नाटिका सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत, आदर्श महाविद्यालय के अध्यक्ष पदमराज मेहता, राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रभारी बेंगलुरु कुमार जिवेन्द्र झा, डॉ. एस. प्रशांत एवं डॉ. ज्योत्सना सेनी ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे ने किया। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से उपस्थित अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।

वंदे मातरम पर संग्राम, प्रियांक खड़गे ने BJP-RSS को घेरा

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com

बेंगलुरु 21 अगस्त 2026। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कर्नाटक की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि यदि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर ने सार्वजनिक रूप से गीत के शुरूआती दो पद गाने के निर्णय का समर्थन किया था, तो क्या आज उन्हें भी राष्ट्र-विरोधी कहा जाएगा? अधूरे वंदे मातरम को लेकर भाजपा का आरोप

विवाद उस समय तेज हुआ जब भाजपा ने कांग्रेस नेताओं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी शामिल हैं, पर दिल्ली और गोवा में हालिया कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण नहीं गाने और राष्ट्रीय गीत का कथित अनादर करने का आरोप लगाया।

इसके जवाब में प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया मंच पर भाजपा पर राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर शासन से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। RSS अपनी शाखाओं से शुरू करे प्रियांक खड़गे ने भाजपा और फरर को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वंदे मातरम को लेकर इतना ही आग्रह है तो इसकी शुरूआत फरर की दैनिक शाखाओं से होनी चाहिए। उन्होंने फरर की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे के स्थान पर वंदे मातरम गाने की बात कही। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम सुनाने की चुनौती दी।

बेरोजगारी और पेपर लीक पर भी साधा निशाना खड़गे ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को लेकर उठाया गया विवाद लोगों का ध्यान बेरोजगारी, पेपर लीक, आर्थिक चुनौतियों और अन्य सार्वजनिक मुद्दों से हटाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि युवाओं की नौकरियों और परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर भी ऐसी ही राजनीतिक सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जाती। उन्होंने कहा कि जब सरकार के सामने जवाबदेही के सवाल खड़े होते हैं, तब नए विवाद खड़े कर चर्चा का रुख बदलने की कोशिश की जाती है। 1937 के प्रस्ताव का दिया हवाला

कांग्रेस ने अपने रुख के समर्थन में 28 अक्टूबर 1937 को कोलकाता में पारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव का हवाला दिया है। कांग्रेस के अनुसार, उस समय राष्ट्रीय एकता और सभी समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल शुरूआती दो पद गाने का निर्णय लिया गया ॰

दक्षिण के मुख्यमंत्रियों ने भरी हामी, परिसीमन पर नहीं बनी बात

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com

चेन्नई, 21 अगस्त 2026। अंतरराज्यीय जल विवादों को बातचीत और आपसी सहमति से जल्द सुलझाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव को दक्षिण भारत के राज्यों ने समर्थन दिया है। गुरुवार को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में जल विवादों के साथ लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। हालांकि, परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएं बरकरार हैं और इस पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। राज्य हित जरूरी, लेकिन विवाद लंबे न खिंचें बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्यों का अपने हितों की रक्षा करना स्वाभाविक है, लेकिन यदि किसी विवाद के कारण वर्षों तक किसी राज्य को पानी से वंचित रहना पड़े और पानी समुद्र में बह जाए तो इससे किसी का हित पूरा नहीं होता। उन्होंने ब्रह्मपुत्र से कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में काम करने की जरूरत बताई। शाह के अनुसार, इससे भारत को आने वाले लंबे समय तक जल संकट से बचाने में मदद मिल सकती है और साथ ही नए जलमार्गों के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की चिंता कायम

बैठक में परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंता के रूप में सामने आया। राज्यों का कहना है कि यदि लोकसभा

सीटों का पुनर्वितरण मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर किया गया तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान हो सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु ने मौजूदा 543 लोकसभा सीटों की संख्या अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखने की मांग की। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाए रखने की मांग रखी। उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा सीटों के भीतर लागू करने का भी सुझाव दिया। मेकेदातु पर तमिलनाडु को भरोसा बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि परियोजना बनने की स्थिति में तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा की जाएगी।

हालांकि, तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि बैठक में कर्नाटक के साथ चल रहे कावेरी जल बंटवारे के विवाद या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़े मामलों पर चर्चा नहीं हुई। आंध्र प्रदेश ने रखा बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कुप्पम के रास्ते अमरावती, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने वाले ट्रांजिट नेटवर्क की भी पैरवी की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई।

केरल ने उठाया मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा केरल की ओर से मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाया गया। राज्य ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सहकारी संघवाद को मजबूत करने की जरूरत बताई। वहीं तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमरका ने कृष्णा नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। पुडुचेरी ने भी सालभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और पड़ोसी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, के सहयोग की आवश्यकता जताई। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक से अंतरराज्यीय जल विवादों को बातचीत से सुलझाने की दिशा में सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन परिसीमन का मुद्दा अभी भी दक्षिणी राज्यों और केंद्र के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती बना हुआ है।

सुनील लखोटिया बने माहेश्वरी संगठन के संभाग उपाध्यक्ष

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com

होसपेट, 21 अगस्त 2026। कर्नाटकझगोवा प्रांतीय माहेश्वरी संगठन के पूर्ण सत्र 2026झ2029 के लिए होसपेट निवासी श्री सुनील कुमार लखोटिया को संभाग उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए जाने पर माहेश्वरी समाज सहित विष्णु समाज के बंधुओं में हर्ष की लहर है। समाजजनों ने लखोटिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की।

इस अवसर पर विष्णु समाज के अध्यक्ष श्री चंदन सिंह भाटी ने श्री सुनीलजी लखोटिया का हार पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि लखोटिया के कुशल नेतृत्व में माहेश्वरी समाज का बहुमुखी विकास होगा तथा संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। कर्नाटकझगोवा प्रांतीय माहेश्वरी संगठन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष श्री रमेशजी बूब, रायचूर, सचिव श्री वेंकटेशजी गिलडा, कलबुर्गी तथा संभाग उपाध्यक्ष श्री सुनीलजी लखोटिया, होसपेट शामिल हैं।

इसके साथ ही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्री राजेश करवा निर्वाचित हुए। श्री पुरुषोत्तम सिंगी, श्री सुशीलजी बूब, श्री नंदकिशोर सिंगी, श्री मनोजी बंग गंगावती तथा श्री गोपालजी चांडक कोप्पल समाज के बंधुओं ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को अनेकानेक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

कार्यक्रम के दौरान श्री जबरसिंह राजपुरोहित सहित समाज के अनेक गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। समाजजनों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी संगठन को मजबूत करने, सामाजिक एकता बढ़ाने और समाजहित के कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रेषकः जबरसिंह राजपुरोहित होसपेट

सेवा की राह पर युवाओं को जोड़ रही संघटन यात्रा

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com

शिवमोग्गा, 21 अगस्त 2026। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद (ABTYP) की ओर से आयोजित संघटन यात्रा के तहत चार वरिष्ठ पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिवमोग्गा पहुंचा। यात्रा का उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के साथ युवाओं को सामाजिक सेवा, संगठनात्मक गतिविधियों और समाजहित के कार्यों से सक्रिय रूप से जोड़ना है। प्रतिनिधिमंडल में ABTYP के उपाध्यक्ष-1 अनंतजी भागरेचा, चोका सत्कार एवं युवा वाहिनी के सह प्रभारी गौतमजी खाबिया, आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल के सह प्रभारी प्रसनजी धोका तथा क्षेत्रीय सहयोगी एवं शाखा प्रभारी मुकेशजी गुगलिया शामिल रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने 19 अगस्त की सुबह बेंगलुरु से यात्रा प्रारंभ की। इसके बाद बेंगलुरु क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के साथ मैसूर, मांड्या, हासन एवं चिक्कमगलुरु का दौरा करते हुए बुधवार दोपहर करीब 1 बजे शिवमोग्गा स्थित तेरापंथ भवन पहुंचा। शिवमोग्गा के बाद यात्रा दावणगेरे, हुब्बल्ली सहित कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों तक जाएगी। युवाओं से सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आान तेरापंथ भवन में आयोजित बैठक में स्थानीय पदाधिकारियों एवं युवाओं ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर तेरापंथ सभा अध्यक्ष उत्तमजी बरलोटा, अणुव्रत समिति अध्यक्ष चंद्र प्रकाशजी छाजेड़, तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष निखिलजी कोठारी एवं सचिव रोहित कोठारी सहित राजेश बातेवरा, प्रज्वल बरलोटा, कुशल बाफना एवं परिषद के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

ABTYP उपाध्यक्ष अनंतजी भागरेचा ने संगठन द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक एवं सेवा गतिविधियों

की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से नेत्रदान अभियान, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव तथा हिट युवाझफिट युवा जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए युवाओं से इनमें सक्रिय भागीदारी का आान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं की ऊर्जा और उत्साह को सही दिशा मिले तो समाज में सकारात्मक एवं व्यापक परिवर्तन संभव है। प्रसनजी धोका, गौतमजी खाबिया एवं मुकेशजी गुगलिया ने भी युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा केवल संचालित गतिविधियों में सहभागी बनने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को पहचानकर नई सेवा योजनाएं शुरू करने की पहल करें। उन्होंने नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, अनुशासन, संगठन के प्रति समर्पण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने पर जोर दिया। संगठन विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर मंथन

बैठक में स्थानीय पदाधिकारियों एवं युवाओं के साथ संगठनात्मक गतिविधियों, सामाजिक सेवा कार्यों तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने शिवमोग्गा इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए युवाओं से भविष्य में भी समाजसेवा एवं संगठन विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने का आान किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि संघटन यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व और स्थानीय इकाइयों के बीच संवाद मजबूत करने तथा युवाओं को सेवा, संगठन और संस्कार से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। शिवमोग्गा तेरापंथ युवक परिषद ने प्रतिनिधिमंडल के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कर्नाटक के आगामी यात्रा कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रेषकः शांतिलाल साकरिया, शिवमोग्गा।

फटकार का बदला या लालच? 10वीं के छात्रों ने की प्रिंसिपल की हत्या

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com

हैदराबाद, 21 अगस्त 2026। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कोंडामल्लेपल्ली में प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस जांच के अनुसार, हत्या के पीछे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों का हाथ था। दोनों ने कथित तौर पर प्रिंसिपल की फटकार और पैसों की चाहत के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ाई है। आखिरी शब्द बना अहम सुराग 11 अगस्त को हत्या से कुछ समय पहले रूपा रेड्डी ने अपनी मौसी को फोन किया था। बातचीत के दौरान उनका आखिरी शब्द बाबू बताया गया। इसके बाद फोन बंद हो गया। पुलिस ने इस सुराग को गंभीरता से लिया और जांच में पाया कि रूपा अपने स्कूल के बच्चों को प्यार से बाबू कहकर बुलाती थीं। पुलिस ने स्कूल के 13 छात्रों में से पांच से पूछताछ की। जांच के दौरान दो छात्रों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिस को पता चला कि दोनों हाल के दिनों में काफी पैसा खर्च कर रहे थे। CCTV और नकदी से खुला राज

जांच के दौरान CCTV फुटेज में दो संदिग्ध छात्रों की गतिविधियां सामने आईं। पुलिस ने डोनियाला एक्स-रोड के पास बाइक से जा रहे दोनों छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके पास से करीब 1.54 लाख रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक, बरामद 500 रुपये के तीन नोटों पर खून के धब्बे भी मिले। पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर प्रिंसिपल की हत्या और घर से नकदी व फोन चोरी करने की बात स्वीकार की। महंगा फोन और मौज-मस्ती का शौक

जांच में सामने आया कि दोनों छात्र एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते थे। पुलिस के अनुसार उन्हें पैसे, महंगे मोबाइल फोन, बाइक और मौज-मस्ती का शौक था। दोनों सोशल मीडिया और YouTube के जरिए जल्दी पैसा कमाने के तरीकों की तलाश कर रहे थे। फटकार से बढ़ी नाराजगी पुलिस जांच के मुताबिक, कुछ समय पहले हॉस्टल में फोन और पैसे मिलने के बाद प्रिंसिपल ने दोनों छात्रों को कक्षा में फटकार लगाई थी। उन्होंने कथित तौर पर उनके व्यवहार की शिकायत परिवार से करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद दोनों छात्रों में प्रिंसिपल के प्रति नाराजगी बढ़ गई।

पुलिस के अनुसार, वारदात से करीब एक सप्ताह पहले दोनों ने कथित तौर पर प्रिंसिपल की गतिविधियों की रेकी की। घटना वाले दिन चाकू और दस्ताने खरीदे गए। पहचान लिए जाने पर किया हमला पुलिस के मुताबिक, वारदात के दौरान प्रिंसिपल ने दोनों को पहचान लिया था। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर उन पर चाकू से करीब 27 बार वार किए। हत्या के बाद नकदी और मोबाइल लेकर दोनों पीछे के रास्ते से फरार हो गए।

डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फोरेंसिक जांच, CCTV फुटेज और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.54 लाख रुपये नकद, मृतका का मोबाइल फोन, कथित हत्या में इस्तेमाल चाकू, दस्ताने और मास्क बरामद करने का दावा किया है। मामले की जांच में पुलिस अब वारदात के अन्य पहलुओं और दोनों छात्रों की भूमिका से जुड़े साक्ष्यों को भी खंगाल रही है।

नागेंद्र पर फिर घिरी सरकार, सदन के बाद भी संघर्ष का ऐलान

भारतार्थ खबर। संवाददाताः धन्नाराम चौधरी Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 21 अगस्त 2026। कर्नाटक में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के कैबिनेट में बने रहने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने नागेंद्र के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद भी इस मुद्दे को लेकर पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। विजयेंद्र के नेतृत्व में विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी समेत भाजपा नेताओं एवं विधायकों ने विधानसभा परिसर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के निकट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की।

मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह जनता के हितों के बजाय भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोगों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दलितों के मुद्दे पर केवल मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वाल्मीकि निगम मामले को लेकर सवाल विजयेंद्र ने वाल्मीकि विकास निगम से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब दलितों के विकास के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग के आरोप सामने आए थे, तब कांग्रेस नेताओं को दलित हितों की चिंता क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार को नागेंद्र को कैबिनेट से हटाकर इस मामले में स्पष्ट संदेश देना चाहिए। नागेंद्र को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा पहले कैबिनेट से हटाए गए नागेंद्र को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करने की परिस्थिति आखिर क्यों बनी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से सवाल किया कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) की जांच में नागेंद्र को क्लीन चिट मिल गई है। विजयेंद्र ने कहा कि जांच जारी रहने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नागेंद्र को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर कांग्रेस सरकार ने राज्य के दलित समुदाय के साथ अन्याय किया है। साथ ही मुख्यमंत्री से नागेंद्र को तत्काल कैबिनेट से हटाने की मांग की।

सदन के बाद भी जारी रहेगा विरोध विजयेंद्र ने कहा कि विधानसभा में सूखा, ङढरउ घोटाले और भ्रष्टाचार समेत कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य की जनता सरकार के कामकाज पर नजर बनाए हुए है और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग लगातार उठाई जाती रहेगी।

हिमाचल कांग्रेस में घमासान, नोटिस के बाद खाची के तेवर तीखे

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com
शिमला, 21 अगस्त 2026। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और नेताओं के बीच बढ़ते टकराव ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठियोग से विधायक एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस ने प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद भी खाची के तेवर नरम नहीं पड़े। उन्होंने खुद को कांग्रेस का बब्बर शेर बताते हुए कहा कि वह राजनीतिक षड्यंत्रों से डरने वाले नहीं हैं। राठौर पर टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद विवाद उस समय सामने आया जब खाची ने ठियोग में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विधायक कुलदीप सिंह राठौर को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि राठौर को ठियोग में 11 लोग भी नहीं जानते। बयान सामने आने के बाद पार्टी के भीतर इसे लेकर नाराजगी बढ़ी और मामला अनुशासन तक पहुंच गया। एक सप्ताह में देना होगा जवाब

प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाची को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जिंटा ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। खाची के किसी अन्य कथित बयान के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मामला सामने आने पर उसकी भी जांच की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह के समर्थन से गरमाई सियासत विवाद के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुलदीप सिंह राठौर के समर्थन में सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी। राठौर ने इसके लिए उनका आभार जताया, हालांकि उन्होंने खाची के बयान पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की।

2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर

प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जमीनी स्तर की गतिविधियों, ब्लॉक कमेटियों को दिए गए लक्ष्यों और जनता के बीच पार्टी के प्रति रुझान की समीक्षा की गई। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से मुकदमे दर्ज कराने के आरोपों को जिंटा ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और विजिलेंस बिना आधार के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कानून का उल्लंघन, संपत्ति संबंधी गड़बड़ी या ठोस शिकायत मिलने पर ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जिंटा ने भाजपा पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ गलत प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को अपने नेताओं और पदाधिकारियों पर लगे आरोपों पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हितों और अधिकारों के लिए निष्पक्षता से काम कर रही है।

NEET में अनिता चौधरी की शानदार सफलता, चेंडा गुरुकुल ने किया सम्मान

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com
चेंडा पाली 21 अगस्त 2026। हुबली-धारवाड़ निवासी अनिता चौधरी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-2026) में शानदार प्रदर्शन कर परिवार, समाज और चेंडा शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया है। अनिता ने NEET-2026 में 720 में से 622 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 4739 प्राप्त की।

अनिता, सुपुत्री श्री लालारामजी भुरिया, मूल निवासी मोतीसरा, सिवाना तथा वर्तमान में हुबली-धारवाड़ में निवासरत हैं। उन्होंने कक्षा 8वीं से 12वीं तक चेंडा गुरुकुल में अध्ययन किया। अपनी लगन, मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने की मजबूत नींव तैयार की है। अनिता की इस उल्लेखनीय सफलता पर कन्या गुरुकुल चेंडा शिक्षण संस्थान की ओर से उनका सम्मान कर उत्साहवर्धन किया गया। संस्थान द्वारा किए गए सम्मान से अनिता का मनोबल बढ़ा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

इस अवसर पर अनिता की सफलता को परिवार और समाज के लिए गौरव का विषय बताया गया। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि मेहनत, संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। अनिता चौधरी की इस उपलब्धि पर परिजनों, समाजबंधुओं एवं शुभचिंतकों ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं प्रेषित कीं।

एटीएम मशीन काटकर लूटने की कोशिश, एक गिरफ्तार

लखनऊ (संवाददाता)। मोहनलालगंज में गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब 12.30 बजे बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। बिना नंबर की सफेद कार से पहुंचे बदमाशों ने एटीएम को काटकर कैश निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान ग्रामीणों को आहट हुई तो उन्होंने शोर मचा दिया। ग्रामीणों को आता देख बदमाश एटीएम की स्क्रीन और कुछ सामान लेकर कार से भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। पुलिस ने एक बदमाश को कार समेत पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि फरार साथी और घटना में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इंडिया वन एटीएम के फ्रेंचाइजी पार्टनर और आलमबाग के मवइया निवासी राहुल गुप्ता ने बताया कि मोहनलालगंज कस्बे में मौरावां रोड पर उनका इंडिया वन एटीएम लगा है। 20,21 अगस्त की रात करीब 12.30 बजे कार से आए कुछ बदमाशों ने एटीएम मशीन का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया। बदमाश स्क्रीन, की-पैड, कार्ड रीडर, मशीन का लोगो और अन्य पुर्जे अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने एटीएम में लगा कैमरा भी तोड़कर चोरी कर लिया। आसपास के लोगों से फोन पर सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे और नुकसान की जानकारी हुई। राहत की बात यह रही कि बदमाश एटीएम से नकदी चोरी करने में सफल नहीं हो सके।

तैलिक साहू राठौर महासभा ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा उत्तर प्रदेश और भाजपा ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय के सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कल्याण सिंह रामभक्त, जनप्रिय नेता और पिछड़े वर्ग के सशक्त प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में राष्ट्रहित और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन को मजबूती मिली और राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा मिली। वक्ताओं ने कहा कि कल्याण सिंह का जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और भाजपा के संगठन में कल्याण सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। इस दौरान सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उन्हें कोटि-कोटि नमन किया।

देशभर में यूपी की राखियों की धूम, ग्रामीण महिलाओं की बनाई राखियों की हाई डिमांड

लखनऊ (संवाददाता)। इस रक्षाबंधन भाइयों की कलाइयों पर उत्तर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता का रंग नजर आएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी करीब 5000 महिलाएं आकर्षक और हस्तनिर्मित राखियां तैयार कर रही हैं। प्रयागराज, वाराणसी, बागपत, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, उन्नाव, शामली, जौनपुर और मिजार्पुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में राखियों का निर्माण हो रहा है। महिलाओं द्वारा तैयार राखियों की स्थानीय बाजारों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मांग बढ़ी है। ई-सरस समेत विभिन्न ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि फरुर्खाबाद और नोएडा के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार राखियों की ई-सरस पर लगातार अच्छी मांग मिल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के कारण ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद अब स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं हैं। ई-कॉमर्स के माध्यम से उन्हें नए ग्राहक मिल रहे हैं। साथ ही पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने का अनुभव भी मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा राखी निर्माण से उनकी आय बढ़ने के साथ ग्रामीण संस्कृति और महिलाओं की रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार के लोकल फॉर लोकल संकल्प को गति मिलेगी और महिला उद्यमिता तथा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की महिम मजबूत होगी।

दिल्ली-सिलीगुड़ी सफर होगा तेज, शाह ने बताया सुरक्षा प्लान

भारतार्थ खबर।
Bhaarataarth.com
सिलीगुड़ी, 21 अगस्त 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सिलीगुड़ी दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा और उत्तर बंगाल के विकास को लेकर केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जवानों से संवाद किया और सीमा सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह ने अपने संबोधन में घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए बिना पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने सीमा सुरक्षा बलों के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर राज्य की पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा। 1139 एकड़ जमीन का किया उल्लेख शाह ने कहा कि पहले सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में काफी देरी हुई। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार ने तेजी से काम करते हुए करीब 45 दिनों में 1,139 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई।

गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा से जुड़े बल किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी को सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर विशेष नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह देश के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भू-भाग है और

इसके आसपास नेपाल तथा भूटान सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। शाह ने कहा कि सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रही है।वन बॉर्डर, वन फोर्स की नीति के तहत एसएसबी को नेपाल और भूटान से लगी सीमाओं की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने एसएसबी जवानों की प्रतिबद्धता और मित्र देशों के साथ उनके समन्वय की भी सराहना की। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा अमृत भारत योजना के तहत सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों के विकास का भी उल्लेख किया गया। सरकार का जोर सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है। पूर्ण वंदे मातरम् के गायन का किया जिक्र अपने संबोधन में अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से हुए पूर्ण वंदे मातरम् के गायन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना को राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति से जोड़ते हुए कहा कि इसके माध्यम से नई पीढ़ी तक राष्ट्रभावना का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी स्मरण किया और भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से जुड़े उनके योगदान का उल्लेख किया।

बीएसएफ परियोजनाओं का भी विस्तार शाह ने कहा कि सीमा पर फेंसिंग घुसपैठ रोकने के प्रभावी उपायों में से एक है। उन्होंने बताया कि जलपाईगुड़ी में बीएसएफ की 12वीं और 19वीं बटालियन के लिए आवासीय एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक जमीन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से सीमा प्रबंधन और प्रभावी बनाया जा सकता है। दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर नजर

उत्तर बंगाल के विकास के संदर्भ में दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी महत्वपूर्ण बताया गया। केंद्र सरकार की वर्ष 2026-27 की बुनियादी ढांचा योजनाओं में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों में दिल्ली-सिलीगुड़ी मार्ग को शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने पर दिल्ली और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। तेज रेल संपर्क से आम यात्रियों के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक क्षेत्रों को भी लाभ मिल सकता है। सुरक्षा बलों की तेज आवाजाही के लिहाज से भी बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश की सीमाओं को सुरक्षित, मजबूत और जीवंत बनाना है। सीमा सुरक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचे और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति के तहत उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम टीम से धक्का-मुक्की, एक घंटे हंगामा

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com
रांची, 21 अगस्त 2026। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रांची नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान गुरुवार को पीएचइडी चौक से बूटी मोड़ तक जमकर हंगामा हुआ। दो मंजिला अवैध मकान तोड़ने पहुंची निगम की टीम का अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया। इस दौरान बड़गाईं अंचल के अमीन से धक्का-मुक्की की गई और पीएचइडी विभाग की ओर से निगम को उपलब्ध कराया गया नक्शा भी फाड़ दिया गया। करीब एक घंटे तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। विरोध के बावजूद नगर निगम की टीम कार्रवाई पर डटी रही और सरकारी जमीन पर बने दो मंजिला अवैध मकान को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने अभियान के दौरान दो अन्य अवैध संरचनाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की। निगम अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई से पहले संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद निगम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।

अमीन और इंफोर्समेंट अधिकारियों से उलझते रहे लोग कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे लोग निगम के अमीन और इंफोर्समेंट अधिकारियों से लगातार बहस और धक्का-मुक्की करते रहे। मौके पर पीसीआर वैन के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात थे। निगमकर्मियों का आरोप है कि पुलिस की ओर से अपेक्षित सहयोग और प्रभावी हस्तक्षेप नहीं मिला। निगम अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने जैसे अभियानों में पुलिस बल का पर्याप्त सहयोग जरूरी है। यदि मौके पर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी नहीं रही, तो भविष्य में इस तरह की कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है।

अलबर्ट एक्का चौक से होर्डिंग और पुराना ट्रैफिक बूथ हटाया इसी अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने अलबर्ट एक्का चौक पर भी कार्रवाई की। यहां अवैध होर्डिंग के साथ वर्षों से अनुपयोगी पड़े पुराने ट्रैफिक बूथ को हटाया गया। इसके अलावा मेन रोड चौड़ीकरण और पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से लगी पुरानी लोहे की रेलिंग को काटकर हटा दिया गया। नगर निगम के पदाधिकारियों के अनुसार, अनुपयोगी और अवैध संरचनाओं को हटाने से सड़क तथा पैदल आवागमन के लिए उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे मेन रोड पर यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ नागरिकों को भी आवाजाही में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मिठाई खाने से दुकानदार ने किया इनकार, मचा हड़कंप

भारतार्थ खबर। Bhaarataarth.com
हमीरपुर, 21 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जांच टीम ने एक मिठाई विक्रेता को दुकान पर रखी सिल्वर वर्क लगी मिठाई खाने के लिए दी, लेकिन दुकानदार ने अधिकारियों के बार-बार कहने के बावजूद मिठाई खाने से इनकार कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिल्वर वर्क लगी मिठाई पर उठे सवाल मौदहा कस्बे में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग एवं प्रशासन की टीम ने विभिन्न मिठाई की दुकानों पर जांच अभियान चलाया। इसी दौरान टीम मां वैष्णो जय भवानी स्वीट हाउस पहुंची। अधिकारियों ने दुकान पर रखी सिल्वर वर्क लगी मिठाई का एक टुकड़ा दुकान संचालक अन्नी बाबा को खाने के लिए दिया। अधिकारियों के आग्रह के बावजूद संचालक ने मिठाई खाने से इनकार कर दिया। इस दौरान हुई बातचीत और कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे दुकानदार द्वारा मिठाई खाने से इनकार किए जाने के बाद एसडीएम करनवीर सिंह के निर्देश पर संबंधित मिठाइयों के नमूने लिए गए। खाद्य विभाग की टीम ने अलग-अलग दुकानों से मिठाइयों के सैंपल एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा। प्रशासन के अनुसार, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंदगी और प्रतिबंधित वर्क भी मिला

खाद्य विभाग की कार्रवाई के दौरान दो दुकानों पर साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। इसके अलावा मिठाइयों में प्रतिबंधित सिल्वर वर्क के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप त्योहारों से पहले प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई की खबर फैलते ही मौदहा कस्बे के अन्य मिठाई विक्रेताओं में भी हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय और कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान मिलावटी या मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की।

श्रीराम कथा में गूंजा मर्यादा और धर्म का संदेश

भारतार्थ खबर। संवाददाताः धन्नाराम चौधरी Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 21 अगस्त 2026। बेंगलुरु के होसूर भण्डे स्थित श्री कृष्णा गौशाला परिसर में मातेश्वरी भक्त मंडल की ओर से आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण रसपान कराया गया। कथा व्यास संत किशोरचन्द रामाणी ने भगवान श्रीराम के जीवन एवं आदर्शों का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को सत्य, मर्यादा, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। संत किशोरचन्द रामाणी ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन केवल कथा सुनने का विषय नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्रीराम ने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा।

उन्होंने कहा कि माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीराम ने राजसुख का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। उनके जीवन से परिवार के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति श्रद्धा तथा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कथा के दौरान संत रामाणी ने श्रीराम जन्म एवं बाल लीलाओं से जुड़े प्रसंगों का भी भावपूर्ण वर्णन किया। कथा जैसे-जैसे आगे बढ़ी, श्रद्धालु भक्ति में भाव-विभोर हो गए और कथा स्थल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। पूरे परिसर में भक्तिमय एवं आध्यात्मिक वातावरण बना रहा।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री कृष्णा गौशाला के संस्थापक संत पुष्करदास जी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कथा स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। नौ दिवसीय श्रीराम कथा के आगामी दिनों में रामायण के विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कथा के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। दूसरे दिन की प्रसादी के लाभार्थी रामाराम एवं अमराराम सोलंकी परिवार रहे।

बीएस-6 वाहनों की खरीद पर पंजीयन एवं मार्गकर में 100 प्रतिशत छूट

लखनऊ (संवाददाता)। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सड़क परिवहन एवं राजामार्ग मंत्रालय भारत सरकार मोर्थ द्वारा परिवर्तन योजना लागू की गयी है जो कि यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं शामली में प्रभावी होगी। योजना में बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 एव बीएस-4 श्रेणी के मालवाहनों में ट्रक एवं बस को बीएस-6 डीजल,सीएनजी अथवा विद्युत इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है। इससे स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल तथा आमजन के हित में परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।इस श्रेणी के बस एवं मालवाहन ट्रक स्वामियों द्वारा वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर निक्षेप प्रमाण-पत्र सीओडी प्राप्त होगा। इससे नए बीएस-6 वाहन खरीदने पर वाहन कर एवं पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा मार्ग कर में 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पुराने बीएस-6 वाहनों को खरीदने पर मार्ग कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at "Maruthi"Plaza"", No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, Advertisement 88676 89130 , RNI No. KNHIN/2026/A5540. E-Mail: news@bhaarataarth.com, Website: bhaarataarth.com, Established: 2026